



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 59] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 1985/फाल्गुन 21, 1906
No. 59] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 1985/PHALGUNA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य एवं पूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 90-आईटी टी सी (पी एन)/84-85
नई दिल्ली, 12 मार्च, 1985

विषय :—दूर संचार परियोजना (6) के लिए जापान की विदेश
आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा विस्तारित
5.43 बिलियन यें के यें क्रेडिट के लिए माल और
सेवाओं के आयात के संबंध में लाइसेंसिंग शर्तें ।

फाइल सं. आई पी सी/23(12)/84-85:—संचार परियोजना
(6) की आयात आवश्यकताओं के विस्तार के लिए जापान की
विदेश-आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा विस्तारित
5.43 बिलियन यें के यें क्रेडिट के अधीन आयात लाइसेंसों के
निर्गमन को प्रोत्साहित करने वाली शर्तें जो प्रस्तुत सार्वजनिक
सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, जानकारी के लिए अधिसूचित
की जाती हैं ।

प्रकाश चन्द्र जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य एवं पूर्ति मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 90-
आईटीसी (पीएन)/84-85 दिनांक 12-3-85 का परिशिष्ट ।

जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा
प्रदान किए गए संचार परियोजना (6) के लिए यें 6.0 बिलियन
के यें क्रेडिट के अधीन माल और सेवाओं के आयात के संबंध में
लाइसेंस शर्तें ।

खंड-1 सामान्य शर्तें :

1(1) डाक एवं तार महानिदेशालय की दूर संचार परियोजना
की आयात आवश्यकताओं को विस्तार करने के लिए जापान की
विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा प्रदान किया
5.43 बिलियन यें का ऋण विकासशील देशों के लिए खोला है ।
सद्वतः इस क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं
और सेवाएं जापान और अन्वबंध-1 की सूची में उद्धृत सभी देशों
में आयात की जा सकती हैं । ये देश इस ऋण के अंतर्गत पात्र
स्रोत देश होंगे ।

1(2) क्रेडिट के अधीन केवल उन्हीं मदों और उन्हीं मूल्य के
लिए लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदे-
शालय, तकनीकी विकास/पंजीगत माल समिति द्वारा विशेष
रूप से गिकामी कर दी गई हो । इस क्रेडिट के अधीन जारी किए

ए आयात लाइसेंस (गो) येन का मूल्य 6,600 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए।

आयात लाइसेंस का मूल्य, राजस्व विभाग (सीमा-शुल्क) द्वारा अधिमन्त्रित विनिमय दर और आयात लाइसेंस जारी करने की तिथि को प्रचलित दर और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी की गई मासिक सूचना सं. 78-आईटीसी (पीएन)/74, दिनांक 6 जून, 1974 के पैरा-2 के अनुसार आयात लाइसेंस में संकोचित दर पर विधिवत किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारी और विदेशी मद्रा के प्राधिकृत व्यापारी आयात लाइसेंस (गो) में विनिर्दिष्ट मद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस, मूल्य के साथ डालेंगे। लाइसेंस पर एक सील "जापानी येन ऋण सं. आई-डीपी-29" होगा। प्रथम और द्वितीय प्रत्येक के लिए लाइसेंस में "एम जेसी" कोड होगा। डी.जी.पी. एण्ड टी. को आयात लाइसेंस भेजने समय मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के पत्र में भी इसे देहगाया जाएगा, जिसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को पठाईकित की जानी चाहिए।

1(3) लागत-बीमा-भाड़ा के आधार पर केवल डी.जी.पी. एण्ड टी. के नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

1(4) डी.जी.पी. एण्ड टी. की सुविधा पर निर्भर करते हुए एक से अधिक आयात लाइसेंस क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते हैं। लेकिन, कुल मूल्य येन 6.0 मिलियन (लागत-बीमा-भाड़ा) येन से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (1) में कहा गया है।

1(5) महानिदेशक, डाक एवं तार द्वारा आवेदन पत्र पर आयात लाइसेंस की वैधता में 12 मास की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान की जाए। आगे और वृद्धि करने के लिए/नया आयात लाइसेंस जारी करने के लिए अनुरोध, यदि कोई हो, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजा जाना चाहिए।

1(6) क्रेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले आयात, आयात लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत् स्थापित संलग्न मान और सेवाओं की सजी तक प्रतिबंधित है।

1(7) विदेशी मद्रा के किसी भी परेण की अनुमति आयात लाइसेंस के प्रति नहीं दी जाएगी। भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता का भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस पर ही प्रभारित किए जाएंगे।

1(8) पक्के आदेश अनुबंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी संभरकों को जहाज पर निःशुल्क के आधार पर दिए जाने चाहिए और वे आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेज दिए जाने चाहिए। भाड़ा बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपये में भारत में देय होगा। "पक्के आदेशों" का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा दिए गए उन क्रय आदेशों से है जो विदेशी संभरक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों या भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो। विदेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्ताओं के आदेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा एप्टिकरण आदेश स्वीकार्य नहीं है।

1(9) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेके की इस शर्त का तब तक अनुपालन किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक कि

ठेके के पूर्ण दस्तावेज आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार महीनों के भीतर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, दिल्ली, ई-1 अनुभाग को नहीं पहुंच जाते हैं। यदि उपर्युक्त पैरा 1(8) में यथा उल्लिखित पक्के आदेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार महीनों के भीतर आदेश व्यर्थ नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उल्लेख करने हुए लाइसेंसधारी को आयात लाइसेंस को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए। आदेश देने की अवधि में वृद्धि के लिए ऐसे आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा। वे अधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि वृद्धि इस लाइसेंस के जारी होने की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे जो कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले की पात्रता के आधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेंगे। जिस-को वे लाइसेंसधारी को प्रेषित करेंगे। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी, आयात लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गारंटी साख्त पत्र स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तत्त्व रुपया जमा करने आदि की स्वीकृति की सुविधाओं की अनुमति देंगे।

1(10) आयात लाइसेंस की स्थापना से चार महीने के भीतर सभी भुगतान अन्तर्ग पूर्ण करने चाहिए। माल वौचर लदान पर उत्पन्न-अल्प भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठेके में नकद आधार पर अर्थात् वित्तदान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। विदेशी संभरक से भारतीय आयातक को किसी भी निष्पत्ति की ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माल के विनिरण की अवधि के लिए ठेके में निम्न-लिखित अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए :—

“राष्ट्रपत्र की प्राप्ति के बाद महीने
परन्तु अधिक से अधिक
के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।”

पोतलदान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह तिथि 31-12-88 के बाद की न हो।

एण्ड-2 सम्भरण ठेके का सम्भारता करते समय ध्यान में रखी जाने वाली विशेष बातें

2(1) ठेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में (येन की भिन्न के दिना) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय रुपये में करना चाहिए।

भारतीय रुपये या किसी अन्य मद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। ऋण आदेश और संभरक द्वारा एप्टिकरण आदेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए।

2(2) ओ ई सी एफ येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) के अधीन माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए मुख्य निर्देश अनुबंध-2 में दिए गए हैं। लेकिन, यदि माल और सेवाओं के लिए औपचारिक खली अन्तराष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति क्रिया विधि अपनाते का विचार है जिसका भुगतान ऋण की प्राप्ति में से किया जाएगा तो इसका पूर्व अनुमोदन तिथि से प्राप्त

किया जाएगा और अधिप्राप्ति क्रियाविधि (यों) अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित भेजे जाएंगे।

माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने से पहले, बोलीदारों के सभी नोटिस और अनुदेशों की प्रतियां, बोली प्रपत्र, प्रस्तावित संविदा, विशिष्टकरणों और ड्राईंग और बोली से सम्बंधित सभी अन्य दस्तावेजों पूर्व अनुमोदन के लिए निधि को प्रस्तुत किए जाएंगे।

सफल बोलीदार के लिए अधिनियम का नोटिस जारी करने से पहले, अधिनियम के लिए बोलियों का विश्लेषण और प्रस्ताव निधि को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ओ ई सी एफ का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त दस्तावेज आवेदन-पत्र, दो प्रतियों में, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) को भेजे जाएंगे।

2(3) विदेशी संभरक का भूगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा 1983-84 के लिए ओ. ई. सी. एफ. येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी-27 के अधीन खोले गए अपरिवर्तनीय साखुपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए। जिसका बदौरे नीचे खण्ड-6 में दिया गया है।

2(4) आयात लाइसेंस के प्राप्ति केवल एक ही संविदा की जानी चाहिए। लेकिन, कुछ विशेष मामलों में, एक से अधिक संविदा करने की अनुमति भी दी जा सकती है। जिसके लिए आयात लाइसेंस जारी होने की विधि के तहत बंद विज्ञापन, आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

2(5) संभरक की पात्रता

संभरक पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रक होंगे या पात्र स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रकों द्वारा शामिल बंध व्यक्ति होंगे।

2(6) संविदा में घोषणा

प्रत्येक संविदा में संभरक द्वारा माल एवं संभरक की पात्रता और संभरक के हस्ताक्षर और तारीख से निम्नलिखित घोषणा जोड़ी जाएगी—

“मैं, अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि संभरित किया जाने वाला माल..... (सम्बन्धित पात्र स्रोत देश का नाम) में उत्पादित है।

“मैं, अधोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोत देशों से आयातित भाग निम्नलिखित सूच के अनुसार 30 प्रतिशत से कम है—

$$\frac{\text{आयातित भारत बीमा भाड़ा मूल्य} + \text{आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100$$

और

“मैं, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि..... (पात्र स्रोत देश का नाम) में..... (कम्पनी का नाम) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रकों द्वारा निर्गमित है।”

2(7) अपात्र स्रोत देशों से अनुमोद आयात

जिन वस्तुओं में अपात्र स्रोत देशों में बनी हुई सामग्री निहित है उसका वित्तदान किया जा सकता है दशवें कि निम्नलिखित सूच

के अनुसार ऐसे उत्पाद का प्रति एकक का मूल्य रु. दस बार आधार पर आयातित भाग 30 प्रतिशत से कम हो :—

$$\frac{\text{आयातित भारत बीमा भाड़ा मूल्य} + \text{आयात शुल्क}}{\text{संभरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य}} \times 100$$

खण्ड- 3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्तें

3(1) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट होने चाहिए :—

(क) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच दूर संचार परियोजना 6 के लिए येन क्रेडिट सं. ओ ई डी पी-27 (परियोजना सहायता) से संबंधित 11 सितम्बर, 1984 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा।

(ख) संभरणों का भूगतान, भारत सरकार और जापानी विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) के बीच येन क्रेडिट सं. आई डी पी-27 से संबंधित 11 सितम्बर, 1984 को हुए ऋण समझौते के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया टोकियो द्वारा जारी किए जाने वाले अपरिवर्तनीय साखुपत्र के माध्यम से किए जाएंगे।

(ग) विदेशी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत होगा जो एक और भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर ओ ई सी एफ द्वारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित हों।

(घ) 2(6) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र (तीन प्रतियों में)

3(2) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय दूतावास, टोकियो के परामर्श पर पात्र परिदहन व्यवस्था करने के लिए सहमत हों और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास, टोकियो को, शामिल मान को संपूर्ण की कार्यक्रम से अवगत करावेगा और पात्र लदान से कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके। विशेष मामलों में, जहां भारतीय आयातक इच्छुक हों, सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक को प्रत्येक पात्रलदान के पश्चात् आवेदनक बदौरे देने हुए तार से सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए।

खण्ड-4 विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) द्वारा ठेके की अनुमोदन

4(1) लाइसेंसधारी को पक्के आदेश देने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर महानिदेशक डाक एवं तार और विदेशी संभरणों दोनों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जो विदेशी संभरणों द्वारा लिखित में पण्डित आवेदन के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियां संगत बैंक आयात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित, जापान अनुभाग, कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

4(2) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषयवस्तु के लिए अनिवार्य आशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों पर भी लागू होगी।

4(3) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) जापान अनुभाग, दूर संचार परियोजना (6) के लिए येन क्रेडिट सं. आई डी पी-27) परियोजना सहायता के अन्तर्गत वित्तदान सहायता करने के लिए विदेशी आर्थिक निधि (ओ ई सी एफ) को सहायता वस्तावजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा।

खण्ड-5 विदेशी संभरकों को भुगतान-साख पत्र क्रियाविधि

5(1) विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) से ठेकों के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जापान अनुभाग द्वारा महानिदेशक, डाक एवं तार और सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक, को उसकी सूचना दी जाएगी। उसके बाद महानिदेशक डाक एवं तार को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रण (जिसे इसके बाद सी. ए. ए. एण्ड ए. कहा गया है) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को अनुबंध-3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। सी. ए. ए. एण्ड ए. संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्न प्रपत्र-4 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा। जो संबंधित विदेशी संभरक के नाम में वास्तविक आयातों के लिए संलग्न अनुबंध-5 के रूप में या (सहायता के लिए) अनुबंध-6 के रूप में अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोकियो शाखा को भेजा जाना चाहिए। प्राधिकार पत्र की प्रतियां विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ), भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और जापान अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

5(2) प्राधिकारपत्र मिलने पर, भारतीय बैंक, टोकियो अनुबंध-5 (वास्तविक आयातों के लिए लागू होता है) या 6 (सहायता के लिए लागू होता है) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय साखपत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ ई सी एफ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा।

सी. ए. ए. एण्ड ए. से प्राधिकार पत्र के आधार पर साख पत्र खोलने के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि सहायता संशोधन या अन्यथा के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पत्र/साख पत्रों के संशोधनों पर स्वतः लागू होगी।

5(3) माल का पोदनदान करने के बाद विदेशी संभरक अपने बैंकरों के माध्यम से साख पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए बैंक आफ इंडिया टोकियो को प्रस्तुत करेगा (यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि को विदेशी संभरक को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद आयातों की लागत की धनराशि की प्रति पूर्ति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा।

5(4) साख-पत्र को खोलने, रख-रखाव और परिचालन पर किए गए सभी खर्च विदेशी संभरको या आयातक के लेखों में जाएंगे और इसलिए ओ ई सी एफ से उनका भुगतान नहीं किया जाएगा।

संभरको को भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्त निःशुल्क माल की लागत के भुगतान की तिथि और ओ ई सी एफ द्वारा प्रतिपूर्ति की तिथि के बीच के समय का ब्याज भारतीय बैंक उनके और भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) के साथ 25-3-80 को हुए समझौते की शर्तों के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी प्रति-पूर्ति भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा की जाएगी। भारतीय दूतावास, जापान द्वारा ब्याज भुगतान पर किया गया रुई डाक एवं तार विभाग [देखें खण्ड-6(4)] से प्राप्त किया जाएगा।

खण्ड-6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

6(1) भारतीय बैंक, टोकियो संगत प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट में संकेतित अनुसार महानिदेशक डाक एवं तार के प्राधिकार, बैंकरों को पराम्य जहाजगनी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी, दिल्ली में खाली के ऊपर बाहनें ओर कोने में कोड नं. 5130000009 का संकेत देते हुए रुपया निक्षेप कर दिया गया है। विदेशी संभरकों को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रूप में सार्वजनिक सूचना सं. 74-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 31-5-1974 में निर्धारित विधि के अनुसार भारत सरकार के लेखों में जमा किए जाने हैं।

विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान के समतुल्य रुपया की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की यह मिश्रित दर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं. 109-आई टी सी (पी एन) 74, दिनांक 3-8-74 और सं. 8-आई टी सी (पी एन) 76, दिनांक 17-1-76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई है जो मुख्य-नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की गई हो। इस संबंध में और व्याज की दर के संबंध में भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिमूचित कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेवारी होगी कि दिये धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी खातों में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। आयातक को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि दिये धनराशि अपने ऋणदाताओं से दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खातों में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए आयातक की जिम्मेवारी होगी कि दिये धनराशि सरकारी खातों में ठीक प्रकार से तुरन्त जमा कर दी है भले ही जब वे विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल की सुपुर्दगी प्राप्त करते हैं। यदि आयातक सरकार को दिये धनराशि का माल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दिया जाए और मामले की रिपोर्ट मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को दी जाय ताकि ऐसे आयातक को आगे और आयात लाइसेंस जारी न किए जाएं। जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपॉजिटर्स एण्ड बान्सिज-843 निविल डिपॉजिटर्स-डिपॉजिटर्स फार परचेजिंग एटस्ट्रा एन्ड एन्ड क्रेडिट्स लोन एग्रीमेंट्स" नोन फ्रॉम दि गवर्नमेंट आफ जपान 5.43 निविल येन क्रेडिट सं. आई डी पी-27 फार दूर संचार परियोजना (6) होना चाहिए। लेकिन 31-5-1974 की उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में दिए गए ब्याज

प्रभारों की गणना और निक्षेप संबंधी व्यवस्थाएँ लागू नहीं होंगी, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विभागों के आयातों के संबंध में व्याज प्रभार वसूल नहीं लिए जाते हैं।

6(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हज़ारी, बिल्ली में चालान के ऊपर दाहिनी ओर क्रॉस में कोड सं. 5130000009 का संकेत दते हुए सरकार की साख में सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/68, दिनांक 30-8-1968, सं. 233-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 24-10-68, सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-71, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-5-74 और सं. 103-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित तरीके से जमा होना चाहिए।

6(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बद्ध भारतीय बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह उतिरिक्त धनराशि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरों को इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 132-आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के पैरा-2 में निर्धारित सूचना चालान के कालम "धन परेक्षण और प्राधिकारी" (यदि कोई हो के पूर्ण व्यौरों) में निरपवाद रूप से निदिष्ट किए गए हैं। खजाना चालान में निम्नलिखित व्यौरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनांक

(ख) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी सभरक का भुगतान करने की तिथि

उसके पश्चात् सी. ए. ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का संदर्भ दते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रूपया जमा करने का साक्ष्य दते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी. ए. ए. एण्ड ए. को भेजा जाना चाहिए।

टिप्पणी.—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रूपया का निक्षेप भारतीय बैंक, टोकियो की अदायगी की सूचना और अपरिवर्तनीय पांत्लदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निरबाध रूप से किया जाना चाहिए और यह कि इसके तत्काल बाद सी. ए. ए. एण्ड ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

6(4) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति पर रूपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठंकन करना चाहिए और अपेक्षित "एस" प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक बंधों का भेजना चाहिए।

भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को दिए गए व्याज प्रभार आदि के अनुसार ही येन भुगतान के तूल्या रूप की गणना की उपयोगित खण्ड 6 की कंडिका 6(1) में

निर्धारित तरीके से की जाएगी और मुख्य लेखाधिकारी के नाम से जमा करा दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, सी. ए. ए. एण्ड ए. इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त परामर्श जारी करेगा।

खण्ड-7 विविध व्यवस्थाएँ

7(1) आयात लाइसेंस के उपयोग करने की रिपोर्टें

आयातक का पोत्लदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साख-पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए।

7(2) सभरकों को विराम शतों के बारे में अधिसूचित करना।

लाइसेंस धारी के आयात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबंधों से सभरक को अवगत करा देना चाहिए जो माल के लान में सभरक पर प्रभाव डालती हैं।

7(3) विवाद

यह सम्भल लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और सभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान में पहले सभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शतों अनुबंध-3 में "भुगतान की शतों" के अंतर्गत अच्छी तरह से स्पष्ट कर लनी चाहिए। संविदा की शतों में विवाद के निपटान से सम्बद्ध व्यवस्थाएँ शामिल होनी चाहिए।

7(4) भविष्य अनुदेश

आयात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामलों या सभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन अडिट सम्भलने (परियोजना सहायता) में आई डी पी-27 के अधीन सभी आभागों को विदेशी आर्थिक निगम निधि, जापान (ओ. ई. सी. एफ.) के साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का लाइसेंस धारी को तत्काल पालन करना होगा।

7(5) अतिक्रमण या उल्लंघन

उपयुक्त खंडों में निर्धारित की गई शतों के अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर उद्घातन-नियम (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्रवाई की जाएगी।

7(6) अनुबंधों की सूची

1. अनुबंध-1 पात्र स्रोत देशों की सूची
2. अनुबंध-2 अधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग वर्शन
3. अनुबंध-3 अधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध
4. अनुबंध-4 प्राधिकार पत्र का प्रपत्र
5. अनुबंध-5 साख पत्र का प्रपत्र (वास्तविक आयातों के लिए लागू)।
6. अनुबंध-6 साख-पत्र का प्रपत्र (सेवाओं के लिए लागू)

अनुबंध-1

पात्र स्रोत देशों की सूची

- (क) विकासशील देश तथा उनके क्षेत्र
- (क-1) विदेशी आर्थिक सहयोग से भिन्न विकासशील देश
- 1 अफ्रीका, उत्तरी सहारा
मिश्र
मोरोको
तनीशिया
 - 2 अफ्रीका, दक्षिणी सहारा
अंगोला
कैमरोन
छाद
मध्य गिनी (1)
छाद
कीनिया
मालागासी गणतंत्र
मारितानिया, मारीशस
पुर्तगाल, गिनी
रवान्डा
सेनेगल से
सोमालिया
टेरी आफर्स और इस्मास
तजानिया गणतंत्र संघ
जाम्बिया
बोत्सवाना
केप वर्डी द्वीप समूह
कमोरो द्वीप समूह
इथोपिया
गिनी
लेसोथो
मालावी
मोजम्बिक
रियूनियम
सेंट हेलेना और
डेप (2)
सैंचिलिज
सूडान
टोगो
अपर वोल्टा
बुरुंडी
केंद्रीय अफ्रीका गणतंत्र
कांगो, दाहोमे का गणतंत्र
जाम्बिया
आइवरी कोस्ट
लाइबेरिया
माली
नाइजर

रोडेशिया

माओ टोम और प्रिन्सिप
मियरा लिओन
स्वाजीलैण्ड
यूगान्डा
जाइरे गणतंत्र

- 3 अमेरिका, उत्तरी और केंद्रीय
बेल्जियम
बरमूडा
डोमिनिकन गणतंत्र
ग्वाटेमाला
जमैका
नीदरलैंड अन्टिलीज
सेन्ट पीट्रो और निकोलस
बारबाडोस
कोस्टारिका
एल सालवाडोर
हेती
मार्टिनिक
निकारगुवा
ट्रिनिडाड और टोबागो,
बोलाइज
क्यूबा
गुआटेमाला
होन्डुरस
मैक्सिको
पनामा
वेस्ट इण्डीज (क्षारा)-एन आई ई
(क) गह-संबंध राजस (1)
(ग) अतिरिक्त (2)
(1) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश, फरोन्डा पो द्वीप सहित
(2) निम्नलिखित द्वीपों सहित :—
असेन्शन, ट्रिस्तन्डा इन एसोसिएट्स, नाइटिंगेल,
राफ
(3) मुख्य द्वीप समूह, अरूबा, बोनाइरे, क्यूराकोओ,
ग्राहा, सेन्ट यूस्टासिय सेन्ट मारटिन (दक्षिण भाग)
- 4 दक्षिणी अमेरिका
अर्जेन्टीना
ब्राजील
फ्रांसिसी गुयाना
पेरू
बोलिविया
कोलम्बिया
गुयाना
सूरिनाम
ब्राजील

पाल्क लैण्ड द्वीप समूह
पराग्वे,
उरुग्वे

5. मध्य-पूर्वी एशिया
बहरीन
लेबनान
यनाइटीड अरब अमीरात,
इजराइल
ओमन
समर अरब गणतंत्र
जोर्डन
मिन्सिआई अरब गणतंत्र
रमन जनवादी का
डी आर. (4)

6. दक्षिण एशिया
अफगानिस्तान
बर्मा
नेपाल
बांग्ला देश
भारत
पाकिस्तान
भूटान
माल द्वीप
श्री लंका

7. सूदूर पूर्वी एशिया
ब्रुनी
कोरिया गणतंत्र
मलेशिया
ताइवान
वियतनाम गणतंत्र
हारकांग
लाओस
फिलिपाइन
थाइलैण्ड
वियतनाम जनवादी गणतंत्र
समर गणतंत्र
मकाओ
सिंगापुर
तिमोर

8. ओशनिया
कोक द्वीप समूह
टामिरी पोलिनेशिया (5),
नॉ हेरिम्स (3), और क्र)
पाण्खा न्यू गिनी
वालिस और फुतुना
फिजी

नाम
मिग्यू
गोलोमन द्वीप समूह (क्रा), टोंगा
पश्चिमी सामोआ
गिल्बर्ट और इलाइस द्वीप
न्यू कैलेडोनिया
पोलिनेशिया द्वीप समूह
(संयुक्त राज्य) (6)

9. यूरोप
माइप्रस
माल्टा
यूगोस्लाविया
जिब्राल्टर
स्पेन
ग्रीक
तुर्की

(1) मुख्य द्वीप एन्टिग्वा, डोमिनिका, ग्रनेडा, सेंट क्रिस्टोफ (सेन्ट क्रिस्टोफो) नेविस-अंगुइला, सेंट वूस्सा और सेंट विसेन्ट ।

(2) सेंट आइलैण्ड, मोन्सेरत, सैमान, तुर्की और काइ-कोस और ब्रिटिश बरजिग द्वीप समूह ।

(3) अजमन, दुबई, फजारा, रम अल सेमाह, शरजाह और उम अल क्वैबत ।

(4) अदन और विभिन्न सल्तनत और अमीरात सहित ।

(5) मोसायटी आईलैंड समूह (ताहिती सहित) को शामिल करने हुए आस्ट्रेल द्वीप समूह, टुआमोट, जार्जिया और ग्रूप और माकेसग द्वीप समूह ।

(6) पॉलिनेशिया द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश, कारोलीन द्वीप समूह, मार्शल द्वीप समूह और मैरिना द्वीप समूह (राम को छोड़कर) ।

(क) 2-ओ. पी. ई. सी. के सदस्य या सहयोगी देश

अल्जीरिया

ग्रेबोन

बेन्ज इला

कंबो

आइ-भावी

बोलिविया

ताइजीरिया

ईरान

कतर

इन्डोनेशिया

लीनियार्ड अरब गणतंत्र

इक्वेडोर

ईराक

सऊदी अरब

अनुबन्ध—2

ओ. ई. सी. एफ. द्वारा व्यवस्थित परियोजना
श्रृणु के अधीन माल और सेवाएं अधिप्राप्ति
करने के लिए मुख्य मार्ग दर्शन

1. विज्ञापन

औपचारिक खूली अंतर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी सवि-
दाएं दोली आमंत्रित करने के लिए श्रृणी देश में सामान्य प्रचार के
लिए कम से कम एक समाचार पत्र में विज्ञापित होना चाहिए।
विज्ञापन के लिए दोली आमंत्रित करने की प्रतियां पात्र श्रोत
देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों को भी तुरन्त प्रेषित की जानी
चाहिये।

2. बोली के दस्तावेज और संविदाएं

2.1 बोली बाण्ड और गारंटियां

बोली बाण्ड या बोली की गारंटियां साधारण आवश्यकताएं
हैं लेकिन, इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित
बोलीकार हतोत्साह हो जाए। बोली खूने के पश्चात् जैसे ही
संभव हो बोली बाण्ड अथवा गारंटियां असफल बोलीकारों को
रिहा कर देनी चाहिए।

2.2 संविदा की शर्तें

संविदा के प्रस्तावन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परि-
वर्तनों में दी गई संविदा की शर्तों में आयातक और ठेकेदार या
संभरक के अधिकार और दायित्व और आयातक द्वारा कोई इन्जी-
नियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और प्राधिकार
एकत्रीकरण रूप से परिभाषित होने चाहिए। संविदा की परम्परा-
गत सामान्य शर्तें, जिनमें कुछ का उल्लेख इन निर्देशन बिन्दुओं
में किया गया है, के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और स्थिति
के लिए उभयैव दिशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए।

2.3 संविदाओं की किस्म और आकार

संविदाएं निष्पादन काम के लिए इकाई मूल्य के या आवेधित
मदों के या एक मूल्य कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के
लिए दोनों के सम्मेलन के आधार पर प्रदान किए जाने वाले माल
या सेवाओं के स्वरूप के अनुसार की जा सकती हैं और बोली
लगाने वाले दस्तावेजों में जनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट
व्याख्या होनी चाहिए।

वास्तविक मूल्य की प्रगति पर मुख्यतः आधारित संविदाएं
विशेष परिस्थितियों को छोड़कर निधि को स्वीकार्य
नहीं हैं।

इजीगिअरिंग उपस्कर और निर्माण के लिए उसी पार्टी द्वारा
प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्न की संविदाएं) यदि
श्रृणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान करते तो
वे स्वीकार्य हैं।

2.4 पात्र संभरक

वे निर्यातक या संभरक जिनके माल एवं सेवाओं का निर्यात
श्रृणु की रक्षा में किया जाना है। (जिसे इसके बाद "पात्र
संभरक" कहा गया है), पात्र श्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे और
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगे :—

- (1) अभिदान किए गए शेषों का एक बड़ा भाग पात्र
श्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा।
- (2) पूर्ण-कालिक निदेशको बहुमत पात्र श्रोत के राष्ट्रिकों
का होगा।
- (3) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों" का पंजीकरण पात्र श्रोत
देशों में होगा।

3.1 संविदा की कीमत

- (क) संविदा कीमत जापान यून में दर्शाई जानी चाहिए
बशर्ते कि संविदा कीमत का यह भाग जो ठेकेदार
श्रृणी के देश में खर्च करेगा, श्रृणी की मुद्रा में
दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) मुख्य समंजन कंडिकाएं

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि
एककी कीमतों में वृद्धि की आवश्यकता है अथवा
बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य है।

यदि संविदा के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात् श्रम और
महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता
है तो संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था
होनी चाहिए। कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट
सूत्र बोली दस्तावेजों में साफ-साफ परिभाषित होना
चाहिए।

माल की स्पष्टाई के लिए संविदाओं में कीमतों के समंजन
की उच्चतम निर्धारित सीमा को भी शामिल किया
जाना चाहिए लेकिन निम्नलिखित कार्यों के लिए संवि-
दाओं में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को
शायद शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्दा किए जाने वाले माल के लिए
मूल्य समंजन की व्यवस्था प्रायः नहीं की जानी
चाहिए।

मार्ग निर्देशन निम्न उन विभिन्न उपबन्धों के परिचय का
आभास नहीं कराती है जिनके द्वारा संविदा मूल्य
समंजित किया जा सके।

(ग) बीमा

माल बोलीदार द्वारा बी जाने वाली चीजों की किस्तों का
बोली दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए।

3.2 दोनों पार्टियों द्वारा निश्चित हस्ताक्षरित संविदा या
विदेशी संभरक द्वारा लिखित रूप में पृष्ठ करण आदेश से
आर्थिक क्रय आदेश जो भारतीय आयातक द्वारा विदेशी संभरक
को दिया गया है, या इनकी फोटो प्रतियां भी फण्ड को स्वी-
कार्य हैं।

3.3 प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित
विवरण जोड़ा जाएगा :—“मैं (हम) एतद्वारा यह उल्लेख करते
हैं कि मेरी (हमारी) कम्पनी पात्र संभरक है क्योंकि शेषों
का—प्रतिशत (%)—(पात्र श्रोत देश) के
राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है, और—प्रतिशत (%)
निदेशक—(पात्र श्रोत देश) के राष्ट्रिक हैं और मेरी
(हमारी) अपनी कम्पनी—(पात्र श्रोत देश) में पंजीकृत
कराई गई है।

4.1 मानदण्ड :—यदि उन राष्ट्रिक मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिसमें अनुसार ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए कि जापान औद्योगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अंतर्राष्ट्रीय मापदण्ड को पूरा करने वाली पण्यवस्तुओं जो मापदण्डों की कोटि के बराबर या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चय करती हैं, उन्हें भी स्वीकार कर लिया जाएगा।

4.2 ब्राण्ड नामों का प्रयोग :—यदि विशेष प्रकार के फाल्तु पत्रों की आवश्यकता है या यह निश्चय किया गया है कि कुछ खास आवश्यक विशेषताओं को बनाए रखने के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की आवश्यकता है तो विशिष्टिकरण निष्पादन क्षमता पर आधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल ब्राण्ड नाम, सूची संख्या और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए। बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्यवस्तुओं के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए। जिनकी विशेषता मिलती जुलती हैं और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बग़ैर निष्पादन और गूण उनमें हैं।

4.3 गारंटी निष्पादन बांड और रोक रखी गई धनराशि :—नागरिक कार्य के लिए बोली दस्तावेज में गारंटी के लिए कुछ जमानत के रूप में होना चाहिए जिससे कि जब तक यह पूरा न हो जाए तब तक काम जारी रहेंगे। यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा निष्पादन बांड द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए जाने के मामले में श्रमों की गुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा को पूर्ण होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए। गारंटी या अपेक्षित बांड की धनराशि में बोली दस्तावेजों में निरूपित किया जाना चाहिए।

माल की स्पष्टता के लिए संविदाओं में आम तौर पर यह वांछनीय होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए रोक रखी गई धनराशि के ही कूल भुगतान का प्रतिशत माना जाए। रोक रखी गई धनराशि को कूल भुगतान की दर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए शर्तें बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट होनी चाहिए। लेकिन, यदि बैंक गारंटी अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र धनराशि के लिए ही होना चाहिए।

5. चुकाई जाने वाली क्षति :—श्रमों को जब कार्य पूर्ण होने या गपदगी में देर होने के कारण फाल्तु खर्चा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली दस्तावेजों में चुकाई जाने वाली क्षति से सम्बन्ध प्रावधान शामिल होने चाहिए। ठेकेदार द्वारा संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले नागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य श्रमों को लाभकारी हो तो ठेकेदार को बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए।

6. बाध्यकारी परिस्थिति :—बोली दस्तावेजों में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि संविदा के अंतर्गत पाटी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उन्मत्त में एक चूक नहीं माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों में (फोर्स मज्योर) के फलस्वरूप हुई है संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी जानी है।

1692 GI/84—2

7. भगड़ों का निपटान :—भगड़ों के निपटान से संबंधित व्यवस्थाएँ संविदा की शर्तों में शामिल की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि व्यवस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमों" पर या अन्य ऐसी व्यवस्थाएँ जो भारतीय आयातक और विदेशी मंत्रक दोनों को स्वीकार्य हों, पर आधारित होनी चाहिए।

8. भाषा की व्याख्या :—बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए। यदि बोली दस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तमाल में लाई जाए तो ऐसे दस्तावेजों में साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए। और इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है।

9. बोली बोलना, मूल्यांकन और ठेका देना

9.1 बोलियों के आमंत्रण और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय :—बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकतर संविदा की महत्वता और पेशवगी पर निर्भर करेगा। साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 30 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए। किन्तु अनुमित समय प्रत्येक परिियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।

9.2 बोली बोलने की क्रिया विधि :—बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए तिथि, समय और स्थान को बोली आमंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए और सभी बोलियाँ निर्धारित समय पर खले आम खोली जानी चाहिए। इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कूल धनराशि जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए।

9.3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन :—बोली खलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़े। आयातक किसी भी बोली बोलने वाले से अपनी बोली के विषय में स्पष्टीकरण के लिए यह कह सकता है लेकिन बोलीकार को उसकी बोली से सारांश एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए।

9.4 गुप्त रखी जाने वाली क्रिया विधि :—कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खलने के बाद बोली से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन और निर्णय में संबंधित सिफारिशों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रिया-विधियों से औपचारिक रूप से संबंधित नहीं है, सब तक नहीं बताया जाना चाहिए जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर दिया जाता है।

9.5 बोलियों की जाच :—बोलियों के खलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या कोई बोलियों के परिवर्तन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई है, क्या बोली दस्तावेज विल्कुल बोलियों के अनुसार है, क्या बोलियाँ जमानतों की व्यवस्था पर रखी गई हैं, तोली दस्तावेज विधिवत हस्ताक्षरित है और क्या बोलियाँ सामान्यतः या अन्यथा रूप से सही हैं, यदि बोलियाँ मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उनमें अस्वीकृत शर्तें हैं या अन्यथा रूप से बोली संबंधी दस्तावेजों के अनुरार नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

इसके बाद प्रत्येक बोली की मूल्यांकन के लिए और बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए।

9.6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएं :—पूर्व योग्यताओं की अनुपस्थिति में आयातक को चाहिए कि वह इस बात पर ध्यान दे कि इस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी बोली का कम से कम मूल्यांकन किया गया है। यदि बोलीकार उन योग्यताओं को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

9.7 बोलियों का मूल्यांकन और मिलान :—बोलियों का मूल्यांकन बोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार होना चाहिए। गणितीय गलतियों के लिए समीक्षित बोली की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों—जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय, उाकरण की कार्य कुशलता एवं क्षमता या फालतू पजों की उपलब्धता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वनीयता को विचार में लिया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में विशिष्टीकृत मानदण्ड के अनुसार रुपये पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समीक्षित कीमत के लिए बृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए।

प्रत्येक बोली में मुद्रा अथवा मुद्राएं जिनमें मूल्य आंका जाता है बोली स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों की तुलना ऋणी द्वारा चुकाई गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए। ऐसे मूल्यांकन में उपयोग के लिए विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय दरों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियां खोलने के दिन उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए। ऐसे मामलों में सफल बोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग में लाई जानी चाहिए।

9.8 बोलियों को अस्वीकृत करना :—बोली दस्तावेजों में सामान्यतया यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी सभी बोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन बोलियों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टीकरण पर नई बोलियां आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए। वह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्तविक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है। सभी बोलियों को अस्वीकार करने के लिए भी तब औचित्य देने चाहिए जहां (क) बोलियां, बोली दस्तावेज के आशय के अनुसार न हो या (ख) बहुत कम प्रति-योगिता है। यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उस कारणों की पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिद्ध की गई है और या तो विशिष्टीकरण के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर (या बोलियों के लिए मूल आमंत्रण में मांगी गई पण्य वस्तुओं की धनराशि पर) या दोनों पर विचार करे। विशेष परिस्थितियों में निर्धारित विचार करने के बाद ऋणी संतोषजनक संविदा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम बोली देने वाले बोलीदार या बोलीदारों के साथ सौदा कर सकता है।

9.9 संविदा का निर्णय :—संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी बोली न्यूनतम मूल्यांकित बोली पर निश्चित की गई है और जो क्षमता और वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है। ऐसे बोलीकार के लिए यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त के रूप में विशिष्टीकरण में निर्धारित पण्य वस्तुओं के लिए या अपनी बोली को परिशोधित करने के लिए जिम्मेदारी ले।

अनुबंध 3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थनापत्र

संख्या.....

दिनांक.....

सेवा में,

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001.

विषय :—येन क्रेडिट ओ ई सी एफ ऋण करार सं.....
के अंतर्गत जापान सेका आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट ओ ई सी एफ ऋण करार सं....
.....के अधीन..... सेके आयात के संबंध में.....
(बैंक का नाम)..... जो कि वही होना चाहिए जो नीचे (क) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक के नाम में साल पत्र खोलने के लिए किया गया है, को प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भारतीय आयातक का नाम और पता

(ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है।

(ग) प्राप्ति के तरीके..... क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है। इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो, कारण सहित यह उल्लेख होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।

(घ) माल का संक्षिप्त विवरण

(ङ) माल का उद्गम देश

(च) यदि कोई हो तो, पत्र से, इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत।

(छ) संविदा का कुल लागत एवं भाड़ा मूल्य (येन में)

(ज) यदि कोई हो तो भारतीय रुपए में देय भारतीय एजेंट के कमीशन की धनराशि (येन में)

- (क) समुद्रपार संभरक को देय वास्तविक लागत एवं भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है ।
- (ख) समुद्रपार के संभरको के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक ।
- (ग) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता
- (घ) वे भूगतान शर्तों और संभावित तिथियां जिनके संविदा के अंतर्गत भूगतान देय होंगे ।
- (ङ) संपूर्णता को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ।
- (च) बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को भूगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)
- (ण) पोतलवान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्टीशिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए)
- (त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता
- (थ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अंतर्गत ओ. ई. सी. एफ. को इसे अधिसूचित किया गया है ।
- (द) क्या साख-पत्र के संचालन और रख-रखाव के लिए बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को देय बैंक खर्च आयातको/या संभरको द्वारा वहन किए जाने हैं ।

अनुबंध 3

प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थनापत्र

संख्या..... दिनांक.....

सेवा में,

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
यू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल,
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001.

विषय :—येन क्रेडिट सं..... (परियोजना सहायता).....
के अन्तर्गत जापान से..... का आयात ।

महोदय,

अपर उल्लिखित येन क्रेडिट सं..... (परियोजना सहायता)
..... के अधीन..... से..... के
आयात के संबंध में.....
(बैंक का नाम)..... जो
कि वही होना चाहिए जो नीचे (ठ) में सम्बद्ध समुद्रपार संभरक
के नाम में साख पत्र खोलने के लिए किया गया है, को प्राधिकार

पत्र जारी करने के लिए हम आपको निम्नलिखित द्वारे प्रस्तुत
करते हैं :—

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता
- (ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और वह तारीख जिस तक वैध है ।
- (ग) प्राप्ति के तरीके..... क्या वह सीधे क्रय या औपचारिक खूले अंतर्राष्ट्रीय निविदा पर आधारित है । इसके मामले में यदि कोई कारण हो तो, कारण सहित यह संकेतित होना चाहिए कि क्या संविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है ।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण
- (ङ) माल का उद्गम देश
- (च) यदि कोई हो तो, पात्र से, इतर स्रोत देशों से आयातित संघटकों का प्रतिशत ।
- (छ) संविदा का कुल जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में)
- (ज) यदि कोई हो तो भारतीय एजेंट के कमीशन की धन-राशि (येन में)
- (झ) वास्तविक जहाज पर निःशुल्क मूल्य (येन में) जिसके लिए प्राधिकार पत्र मांगा गया है ।
- (ञ) समुद्रपार के संभरक के साथ की गई संविदा की संख्या एवं दिनांक
- (ट) समुद्रपार के संभरक का नाम और पता
- (1) राष्ट्रीयता
- (2) पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रको द्वारा लिए गए शेषों का प्रतिशत
- (3) प्रतिनिधि की राष्ट्रकता और/ या संभरक का निवास स्थान ।
- (4) उन निवेशकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक हैं ।
- (ठ) वे भूगतान शर्तों और संभावित तिथियां जिनके संविदा के अंतर्गत भूगतान देय होंगे ।
- (ड) संपूर्णता को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि ।
- (ढ) बैंक आफ इण्डिया, टोकियो को भूगतान करते समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान दिखाते हुए)
- (ण) पोतलवान अनुदेश (वाहनान्तरण/पार्टीशिपमेंट की अनुमति दी गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए)
- (त) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता
- (थ) क्या उसी लाइसेंस के अंतर्गत संविदा (संविदाएं) कर दी गई है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा की संख्या, दिनांक और मूल्य और वित्त मंत्रालय का वह संदर्भ जिसके अंतर्गत ओ. ई. सी. एफ. को इसे अधिसूचित किया गया है ।

(द) क्या साख-पत्र को संचालन और रख-रखाव के लिए बैंक आफ इंडिया- टोकियो को देय बैंक खर्चे आयातकों/या संभरकों द्वारा वहन किए जाने हैं।

(ध) आयातक द्वारा वचनबद्धता :—

“हम एतद्वारा सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से और दर से विदेशी संभरक को किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये को पूरा और सही जमा करने का वचन देते हैं। प्रत्येक निक्षेप माल (आयातित सामग्री) की सुपुर्गगी मौपने से पूर्व तत्काल ही धन-राशियां जमा कराई जाएंगी। विदेशी राष्ट्रीयता वालों की सेवाओं के लिए भुगतानों के मामले में, दिए गए ज्यों ही विदेशी संभरकों के सम्बद्ध बीजक हमारे द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएं और संभरकों को भुगतान कर दिया जाए, त्योंही धनराशियां जमा करा दी जाएं।

अनुबन्ध—4

प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

संख्या एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

बैंक आफ इण्डिया,

टोकियो शाखा,

टोकियो (जापान)

विषय :—येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) ऋण करार सं. के अधीन आयात साख-पत्र खोलने के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 25-3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्वारा यथा संलग्न ब्यापार के अनुसार सर्व श्री के नाम में येन धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

आपके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति आयातक के बैंक, ओ. ई. सी. एफ. भारतीय वृतावास, टोकियो और हमें पृष्ठांकित की जाए।

साखपत्र की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान आपकी निधि से किया जाएगा। भुगतान के साथ ओ. ई. सी. एफ. को आवश्यक दस्तावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का वादा तत्काल करना चाहिए।

संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और ओ. ई. सी. एफ. द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि से दोनों के बीच के समय के लिए उपयुक्त समझौते के अनुसार भारतीय वृतावास, टोकियो द्वारा ब्याज दिया जाएगा। बैंकों के अन्य

खर्चे जिसमें साखपत्र खोलने, रख-रखाव करने और साखपत्रों को जारी रखने के लिए खर्चे भी शामिल हैं क्योंकि वे भी पर-क्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित हैं और यदि कोई हो तो, विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्चे भी विदेशी संभरक को ही देने पड़ेंगे और इसलिए आयातक द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा और इसलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का वादा ओ. ई. सी. एफ. में नहीं किया जा सकता।

जैसे ही आपके द्वारा कोई भुगतान किया जाता है और उसकी प्रतिपूर्ति आपको कर दी जाती है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को भेज दी जानी चाहिए।

यह प्राधिकार पत्र समुद्रपार संभरकों के नाम में साखपत्र खोलने के लिए है इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के मसूदे खोले गए आर्थिक नए साख पत्र या साख-पत्र में बाव के संशोधनों का अनुपालन नहीं किया जाएगा।

यह प्राधिकार पत्र तक वैध रहेगा।

भवदीय

लेखा अधिकारी

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :—

1. आयातक को उनके पत्र सं. दिनांक के के संदर्भ में।

उनसे अनुरोध है कि वे बैंकों से विनियम्य दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकों के माध्यम से रुपये निक्षेप आदि जमा कराने का प्रबंध करें। अपवाद परिस्थितियों के रूप में यदि माल की डिलीवरी सीधे ही सीमा-शुल्क और पतन प्राधिकारियों से मूल पोतलदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली जाती है, तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए। विदेशी राष्ट्रीयता वालों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में जैसे ही सम्बद्ध बीजक भुगतान द्वारा अनुमोदित हो जाएं, निक्षेप कर दिए जाएं/निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में उल्लिखित आवश्यक कार्रवाई की जाए।

2. आयातक के बैंकर। उनसे निवेदन किया जाता कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरक को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चूकाई गई धनराशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आई टी सी (पी एन)/76, दिनांक 17-1-76 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित दर पर की जाएगी। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक की सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सेट दिए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है।

ये धनराशियां या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में चालान के वाहिनी ओर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए। इस संबंध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 184-आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 30-8-68, 233-आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 24-10-68, 132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनांक 5-10-1971, सं. 74-आई टी सी (पी एन)/74-दिनांक 31-5-1974 एवं सं. 103 आई टी सी

(पी एन)/76 दिनांक 12-10-1976 में दिए गए प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है। यह लेखा शीर्ष जिसमें रूपया जमा कराना है वह "क्रेडिट/डिबिट्स एण्ड एडवांसिज-843-सिविल डिपॉजिट्स-डिपॉजिट्स फार परचेजिज एटसेट्स अन्डा एंडर परचेजिज अंडर क्रेडिट/लोन एग्रीमेंट्स"—लोन फ्राम व गर्वनमेन्ट आफ जापान 5.43 विलियन येन क्रेडिट (परियोजना सहायता) सं. आई डी पी-27 फार 1983-84 है।

जिन मामलों में तृल्य रूपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी में सार्वजनिक सूचना संख्या-132 आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किया जाता है, उनके चालान की मूल रूप से एक प्रतिलिपि बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए अग्रपेण पत्र सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी :—

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
पहली मंजिल, थू. सी. ओ. बैंक बिल्डिंग,
मंसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जिन मामले में तृल्य रूपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में, जमा किए गए तृल्य रूपये का पूरा व्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

यदि कोई हो तो, बैंक के खर्चे, ब्याज और बैंक आफ इंडिया, टोकियो शाखा की अन्य खर्चे (जिसमें विदेशी संभरकों के बैंकों के खर्चे भी शामिल हैं) प्रमुख लेखाधिकारी विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली को समतृल्य रूपए अवा करने पर ही तय किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा उचित सूचना बैंक आफ इंडिया, टोकियो, भारतीय दूतावास जापान से सम्बद्ध सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी।

3. निदेशक, ऋण विभाग-2 समुद्रपार अर्थिक सहयोग निधि, टेकवसी म्यूडो बिल्डिंग, 4-1, ओहाटमंची-1-कोमो, चियोडा-कू टोकियो-100 जापान।
4. भारतीय दूतावास टोकियो।
5. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली।

—(लेखा अधिकारी)

अनुबंध-5

(ओ. ई. सी. एफ. एल. सी. -1 प्रपत्र)

अपरिवर्तनीय साख पत्र

(माल के लिए लागू)

दिनांक

सेवा में,

प्रिय महोदय
यह साख पत्र ऋणों और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि की बीच हुए ऋण करार सं.
(संभरक का नाम और पता)

दिनांक के अनुसरण में जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक के पूरे मूल्य के लिए धर्शनी हुण्डी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं. खोले दिया है जो येन (. येन कह सकते हैं) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है। इसे निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भेजा जाना है :—

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक

क्लीन आन बोर्ड, समुद्री पोते लवान बिल जिनमें दिए गए आदेशों का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फ्रेट" एवं "नोटिफाइ"

अन्य दस्तावेज जिसमें से तक लवान का सत्यापन दिया गया हो [संदिग्ध सं. (यदि कोई हो)] के संदर्भ में संक्षिप्त विवरण आंशिक पोतलदान स्वीकृत है। बाह्यान्तरण स्वीकृत है।

पोतलवान बिल जो से बाव की तिथि का नहीं होना चाहिए। आदेशिती को 19 तक अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी डाफ्ट और दस्तावेजों पर यह अंकन होना चाहिए। "अपरिवर्तनीय साखपत्र सं. दिनांक 19 के अंतर्गत निकलवाया गया और आयात संदर्भ सं. (संख्याएं) यदि कोई हो, यह क्रेडिट हस्तान्तरण नहीं है।"

हम एतद् द्वारा बचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत और इसकी शर्तों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी डाफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की संपूर्ण पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तार पूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार डाक्यूमेंट्स क्रेडिटस (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स, पब्लिकेशन सं. 290" के अधीन है।

सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश :—

1. उपर्युक्त ऋण करार के अंतर्गत जारी किए गए बचन पत्र की व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि द्वारा हमारे भगतान के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाव हम बचन देते हैं कि हम सौदा करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की धनराशि को लौटा देंगे।

2. सौदा करने वाले बैंक को यह बताते हुए हम डाफ्ट और दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य

भेजें कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा को भेज दिए गए हैं ।

3. इस क्रेडिट के अंतर्गत सभी बैंक के खर्चे आयातक/संभरक के लेखों के लिए हैं ।

भवदीय,
(.)
वाणिज्यिक बैंक

द्वारा
प्राधिकृत हस्ताक्षर

भुगतान शर्तें

यह भुगतान हमारी साख पत्र सं. का अभिन्न अंग है ।

1. प्रारंभिक भुगतान

धनराशि येन जो कि कूल
संविदा मूल्य के प्रतिशत है ।

अर्पित दस्तावेज
प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

2. मध्यवर्ती भुगतान (यदि कोई हो)

धनराशि येन
जो कि कूल संविदा मूल्य का
प्रतिशत है ।

अर्पित दस्तावेज
प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि

3. फाइनल दस्तावेजों के मूखे भुगतान

धनराशि येन
संविदा के कूल मूल्य का
प्रतिशत है ।

टिप्पणी :—पीलवान दस्तावेजों के मूखे पूर्ण भुगतान के मामले में इस संलग्न दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है ।

अनुबंध-6

(प्रपत्र ओ ई सी एफ एल सी-2)

अपरिवर्तनीय साख पत्र)

(सेवाओं के लिए लागू)

वितांक

सेवा में,

यह साख पत्र ऋणी और विदेशी आर्थिक

,
,
,

(संभरक का नाम व पता)

सहयोग निधि के बीच हुए ऋण

करार सं. दिनांक

. के अनुसारण में जारी
किया गया है ।

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए पूर्ण व्यौर मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए आपके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साख पत्र सं. खोल दिया है जो येन (येन पहले) की कूल धनराशि से अधिक नहीं है ।

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अर्पित (संविदा और परियोजना) से संबंधित दस्तावेजों को नत्थी करना है सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए ।

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साख पत्र सं. दिनांक के अंतर्गत भूना लिए गए है से चिन्हित होना चाहिए ।

यह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है ।

हम एट द्वारा वचन देते हैं कि इस क्रेडिट के अंतर्गत इसकी शर्तों का अनुपालन करके भुनाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर और आदेशिती को दस्तावेजों की संपूर्ण पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे ।

जब तक अन्यथा रूप से विस्तार पूर्वक न बताया जाए, यह क्रेडिट "यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार ड्राफ्टमेंटरी क्रेडिट्स (1974 रिवीजन) इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स नं. 290" के अधीन है ।

सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुरोध :

1. इसमें संलग्न प्रपत्र के अनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत अधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के मूल विवरण की प्राप्ति के पश्चात् इस क्रेडिट के अंतर्गत भुगतान इसमें संलग्न शीट में निर्धारित भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाने चाहिए । प्रारंभिक भुगतान के मामले में उपयुक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की आवश्यकता है ।

2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचनद्वयता पत्र के उपबन्धों के अनुसार विदेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का मूल तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परेषित करने का वचन देते हैं ।

3. उपयुक्त मत्र 1 में यथा उल्लिखित दस्तावेज की एक प्रति और मसौवे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे जाएंगे ।

4. इस साख के अंतर्गत बैंक को सभी खर्चे संभरकों को लेखे के लिए हैं ।

भवदीय,
(वाणिज्य बैंक)

द्वारा
(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

भुगतान अनुसूची

यह भुगतान अनुसूची हमारे साख पत्र सं. का एक अभिन्न अंग है ।

1. प्रारम्भिक भुगतान

धनराशि येन

कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है ।

अपेक्षित वस्तावेज लाभकारी विवरण की अंतिम भुगतान तिथि

2. भुगतान वृद्धि

सम्पूर्ण योग की धनराशि येन

कुल संविदा मूल्य का प्रतिशत है ।

निम्न प्रकार संविदा से भुगतान किया जाना है :—

दिये धनराशि अंतिम भुगतान तिथि

येन

पहली किस्त येन

दूसरी किस्त येन

.

अपेक्षित वस्तावेज (श्रेणी अथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी) द्वारा जारी किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र संलग्न है ।

निष्पादन का विवरण

दिनांक

संदर्भ

सेवा में,

.
.
.

(संभरक का नाम और पता)

संदर्भ :—श्रेण करार सं. के अंतर्गत
. परियोजना से संबंधित
के नाम में येन के लिए
द्वारा जारी किए गए साथ पत्र की सं.
दिनांक में, अधोहस्ताक्षरी,
प्रतिनिध (श्रेण) एतद्द्वारा
और के बीच समझौता सं.
दिनांक में निहित भुगतान की शर्तों के
अनुसार समुद्रपार आर्थिक सहायता निधि द्वारा
की धनराशि (. येन केवल)
प्राप्त करने के लिए एक निष्पादन विवरण जारी करता है ।

(.)

(श्रेणी)

द्वारा

(प्राधिकार हस्ताक्षर)

विशेष अनुदेश :—

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा ।

MINISTRY OF COMMERCE & SUPPLY
(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 90-ITC(PN)/84-85

New Delhi, the 12th March, 1985

Subject : Licensing Conditions in respect of imports of goods and services under the Yen Credit of Yen 5.43 Billion for Telecommunication Project (VI) extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

File No. IPC/23(12)/84-85:—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the 5.43 Billion credit extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Telecommunication Project (VI) as given in Appendix to this Public Notice, are notified for information.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports & Exports

APPENDIX TO MINISTRY OF COMMERCE & SUPPLY
PUBLIC NOTICE NO. 90-ITC(PN)/84-85 DATED THE
12TH MARCH, 1985.

Licensing Conditions in respect of Imports of Goods and Services under the Yen credit of Yen 5.43 Billion for Telecommunications Project (VI) extended by the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) of Japan.

Section I. General Conditions:

I. (i) The Yen Credit of 5.43 Billion extended by the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) for financing the import requirements of the Telecommunications Project of the DGP&T is untied in favour of developing countries. Accordingly the goods and services to be procured under this credit can be imported from Japan and all countries enumerated in the list at Annexure-I which will be eligible source countries under the credit.

(ii) Import Licence(s) under the Credit can be issued only for such items and for such value as have been specifically cleared by the DGTD/CG Committee. The value of import licence(s) issued under this credit should not exceed Yen 6.0 Billion (CIF).

The rupee value of the import licence shall be determined with reference to the exchange rate notified by the Department of Revenue (Customs) and prevailing on the date of issue of the import licence and indicated in the body of the import licence(s) as per para 2 of the Public Notice No. 78.ITC(PN)/74 dated the 6th June, 1974 issued by the CCI&E, which also enjoins that the Customs Authorities and the authorised dealers in foreign exchange will make debits to the value of the licence(s) at the exchange rate specified on the import licence(s). The licence will bear the superscription "Japanese Yen Credit No. ID-P.27". The first and second suffix to the licence code will be "S/JC". This will also be repeated in the letter from the CCI&E forwarding the import licence to DGP&T, a copy of which should be endorsed to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section).

(iii) Import licence(s) can be issued only in favour of DGP&T on CIF basis.

(iv) Depending on the convenience of DGP&T more than one import licence may be issued under this credit, but the total value must not exceed Yen 6.0 Billion (CIF) as specified at (i) above.

(v) The extension of validity of the Import Licence, may on application by DGP&T, be granted for a further period of 12 months. Requests for further extension/issue of fresh import licence, if any, should be referred to the Deptt. of Economic Affairs (Japan Section).

(vi) Import to be financed under the Credit are restricted to the list of goods and services attached to the import licence, duly attested by the licensing authorities.

I (vii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence. Any payment towards Indian Agents' commission should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, therefore, be charged to the licence.

I (viii) Firm order must be placed on FOB basis on the Overseas supplier located in the countries mentioned in Annexure-I and sent to the Department of Economic Affairs (Japan Section) within 4 months from the date of issue of the import licence. Freight and insurance charges will be payable in India in Indian rupees. "Firm orders" means purchase orders placed by the Indian licensee on the overseas supplier duly signed by the latter of purchase contract duly signed by both the Indian importer and the overseas suppliers. Orders on Indian Agents of overseas suppliers and/or order confirmation of such Indian Agents are not acceptable.

I (ix) This condition of the placement of contracts within 4 months period will be treated as not having been complied with unless complete contract documents reach the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Japan Section) within four months from the date of issue of the import licence. If firm orders as explained in para I (viii) above cannot be placed within four months for valid reasons, the licensee should submit the import licence to the concerned licensing authorities giving reasons why ordering could not be completed within four months. Such requests for extension in the ordering period will be considered on merit by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 4 months. If, however, extension is sought beyond 8 months from the date of issue of the import licence such proposals will invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, North Block, New Delhi who will consider such extension on the merits of each case and communicate their decision to the licensing authorities for communication to the licensee. Only on production by the licensee of a letter from the licensing authorities sanctioning such extension will the authorised dealers and departmental authorities permit the facility of letter of authority for the establishment of letter of credit, acceptance of deposits of the rupee equivalent, etc. in respect of supply contracts entered into under the import licence.

I (x) All payments must be completed within 4 months from the expiry of the import licence. Individual payments must be arranged upon shipment of goods. The contract should provide for payment on cash basis i.e. on presentation of shipping documents. No credit facility of any kind will be permitted to be availed of by the Indian importer from the overseas supplier. The contract should provide for the period of delivery of goods as follows:

Months after the receipt of Letter of credit but to be completed latest by the end of "

In fixing the terminal date for shipment it should be noted that this date should not be beyond 31.12.88.

Section—II Special points to be kept in view while negotiating a supply contract

II (i) The FOB value of the contract should be expressed in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's commission, if any, which should be paid in Indian rupees.

In no circumstances the contract value should be expressed in Indian rupees or in any other currency. The purchase order and the supplier's order confirmation should be in English only.

II (ii) The broad guidelines for procurement of goods and services under the OECF Yen Credit (Project Aid) are given in Annexure II. However prior approval of the Fund shall be obtained if it is proposed to adopt procurement procedures other than Formal Open International Tendering for goods and services to be financed out of the proceeds of the loan submitting to the Fund an application for approval of procurement method(s) signed by duly authorised person.

Prior to inviting bids for the procurement of goods and services, the copies of all notices and instructions to bidders, the bid form, the proposed contract, specifications and drawings and all other documents relevant to the bidding shall be submitted to the Fund for its prior approval.

Prior to issuing a notice of award to the successful bidder, the analysis of bids and the proposal for award shall be submitted to the Fund for its approval. The above documents/application may be forwarded, in duplicate, to the Deptt. of Economic Affairs (Japan Section) for obtaining approval of OECF.

II (ii) The payment to the overseas supplier should be arranged through an irrevocable letter of credit to be opened by the Bank of India, Tokyo in their favour under the OECF Yen Credit (Project Aid) No ID-P 27 for 1983-84 the details of which are given in Section VI below.

II (iv) Only one contract should be entered into against the import licence. In exceptional cases, more than one contract may be permitted to be entered into, for which prior approval of the Department of Economic Affairs (Japan Section), Ministry of Finance, should be obtained soon after the date of issue of the import licence.

II (v) Eligibility of Supplier

Suppliers shall be nationals of the eligible source countries or juridical persons incorporated and registered in the eligible source countries and controlled by nationals of the eligible source country concerned.

II (v) Declaration in Contract

The following declaration as to the eligibility of goods and supplier signed and dated by the supplier, shall be attached to each contract—

"I, the undersigned, hereby certify that the goods to be supplied are produced in—(name of the eligible source country concerned)

"I, the undersigned, further certify that to the best of my information and belief, the portion imported from the non-eligible source countries is less than thirty per cent (30%) in accordance with the following formula:

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100 \text{ ' and }$$

"I, the undersigned hereby certify that—(Name of company) has been incorporated and registered in—(name of eligible source country), and is controlled by nationals of—(name of the eligible source countries concerned) "

II (vii) Permissible imports from non-eligible source countries

Financing of goods which contain materials originating from a non-eligible source country or countries may be made, provided that the imported portion is less than thirty per cent (30%) of the price per unit of such products in accordance with the following formula—

$$\frac{\text{Imported CIF Price} + \text{Import Duty}}{\text{Supplier's FOB Price}} \times 100$$

Section III Conditions to be incorporated in the supply Contracts

III (i) The following provisions should be specifically embodied in the supply contract

(a) The contract is arranged in accordance with the Loan Agreement between the Government of India and Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF) dated the 11th September, 1984 concerning the Yen credit No ID-P 27 (Project Aid) for Telecommunications Project (VI) and will be subject to the approval of Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund.

(b) Payments to the supplier shall be made through an irrevocable letter of Credit to be issued by the Bank of India, Tokyo under the Loan Agreement No. ID-P.27 dated 11th September, 1984 between the Government of India and the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

(c) The Overseas suppliers agree to furnish such information and documents as may be required under the Yen credit arrangements by the Government of India on the one hand and the OECF on the other.

(d) Certificates (triplicate) in the forms indicated in II (vi).

III. (ii) In case the supplier is located in Japan, the supply contract should contain a clause that the Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India at least six in advance of the shipping required so that suitable arrangements could be made. In exceptional cases, where the Indian importers require it, this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section IV. Contract Approval by OECF.

IV. (i) Within the stipulated period for placement of firm orders the licensee should forward 4 copies of the contract duly signed by both DGP&T and overseas suppliers supported by order confirmation in writing by the overseas supplier or their photo copies complete in all respects, together with two photo copies of the relevant valid import licence, to Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

IV. (ii) The above procedure will also apply to all contract-amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

IV. (iii) The Ministry of Finance (DEA), Japan Section will arrange to send one copy of the contract documents to the OECF for their approval for financing under Yen credit No. ID-P.27 (Project Aid) for Telecommunication Project (VI).

Section V. Payment to the overseas suppliers—Letter of Credit procedure.

V. (i) On receipt of the intimation of the contract approval from the OECF, by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Japan Section, DGP&T and the CAAA will be informed of the same. Whereafter the DGP&T should approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (hereinafter referred to as CAA&A) Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi with a request in the form attached as Annexure-III for issue of letter of authorisation. The CAA&A will issue a letter of authorisation as in the form attached as Annexure-IV addressed to the Tokyo Branch of the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit as in the form attached as Annexure-V (for physical imports) or Annexure-VI (for services) in favour of the Overseas supplier concerned. Copies of the Letter of Authorisation will be endorsed to the OECF, the Embassy of India, Tokyo, the importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

V. (ii) On receipt of the letter of authority, the Bank of India, Tokyo, will establish an irrevocable letter of credit as per Annexure-V (applicable to physical imports) or VI (applicable to services) in favour of the overseas suppliers concerned and will also forward a copy of the same to the OECF, Embassy of India, Tokyo the importer's Bank in India and the CAA&A.

1692 GI/84—3

The above procedure of opening of letters of credit on the basis of the letters of authority from CAA&A would ipso facto apply to all such amendments to letter of authorisation/letter of credit as may become necessary due to contract amendment or otherwise.

V. (iii) The overseas supplier shall, after effecting shipment of the goods, present through his bankers the documents specified in the letter of credit to the Bank of India, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the overseas supplier through his bankers and will thereafter obtain reimbursement of the said amount from the OECF.

V. (iv) All charges on account of opening, maintenance and on the operation of the letter of Credit will be to the account of the importer/overseas suppliers and hence not reimbursable from OECF.

For the time lag between the dates of payment of the F.O.B. cost of the material by the B.O.I., Tokyo to the suppliers and the date of reimbursement by the OECF to the B.O.I., Tokyo will charge interest as per the terms and conditions of the Agreement entered into by them with the Government of India (Ministry of Finance) on 25-3-1980 and get the same reimbursed by the Embassy of India, Tokyo. The expenditure on account of this interest-payment by the Embassy of India in Japan will be recovered from the P&T Department [vide Section VI (iv)] infra.

Section VI. Responsibility for rupee deposit.

VI. (i) The Bank of India, Tokyo will forward the negotiable shipping documents to the accredited bankers of DGP&T as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Authority and the bankers will in turn ensure that the DGP&T make the rupee deposits at RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or S.B.I., Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping documents. The rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas supplier are to be deposited into Government of India Account in the manner prescribed in Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payments made to the overseas suppliers will be the composite rate of exchange applicable to the date of payment which will be worked out in accordance with the method prescribed in Public Notices No. 109-ITC(PN)/74 dated 3-8-1974 and No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian Bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before the import documents are handed over to the Importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their Bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into the Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further JAS to him may be stopped and the matter reported to the CCI&E so that no further import license is issued to such an importer. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K—Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposits for purchase etc. abroad—Purchase under credits/Loan Agreements"—Loans from the Government of Japan—5.43 billion Yen credit No. ID-P.27 for Telecommunications Project (VI). The provisions regarding calculation and deposit of interest charges mentioned in the above said Public Notice of 31-5-1974 will however not be applicable, as no interest charges are recoverable in respect of imports made by Central Government departments.

VI. (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the

Reserve Bank of India, New Delhi indicating Code No. 513000009 on the right hand corner of the Challan or State Bank of India, 15 Hazart, Delhi as contemplated in Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, No. 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

VI. (iii) The concerned Bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, on account of service charges within seven days after such a demand is made by Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs). While filing in the various columns in the challan it should be ensured by the importers/their bankers that the information prescribed in para 2 of Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5-10-1971 is invariably indicated in the column "Full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the treasury challans:—

- (a) Ministry of Finance letter of authority No. and Date.
- (b) Amount of Yen currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.
- (c) Date of payment to the overseas supplier.

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the letter of authorisation issued by him and also enclosing copies of the invoice and shipping documents.

Note : Importers Banks in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payments and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DFA), New Delhi is kept informed of the fact immediately thereafter.

VI. (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite 'S' Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

The rupee equivalents of Yen payments on account of interest charges etc., made by Embassy of India, Tokyo, to B.O.I., Tokyo will also be calculated in the manner laid down in para VI (i) of Section VI above and deposited in favour of the Principal Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi, for which purpose, CAA&A will be issuing suitable advices.

Section VII. Miscellaneous provisions

VII. (i) Reports on the utilization of the import licence. The importer should send a monthly report, after the letter of credit has been opened regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi.

VII. (ii) Notifying Suppliers of Special Conditions.—The licensee should apprise the supplier of any special provisions in the Import licence which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

VII. (iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-III under "Terms of Payment". Provisions dealing with settlement of disputes should be included in the conditions of contract.

VII. (iv) Future Instructions.—The licensee shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding

any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Yen credit Agreement (Project Aid) No. ID-P.27 with the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF).

VII. (v) Breach or violation.—Any breach or violation of the conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

VII. (vi) List of Annexures :

- Annexure—I List of eligible source countries.
- Annexure—II Main Guidelines for Procurement.
- Annexure—III Request for issue of Letter of Authority.
- Annexure—IV Form of Letter of Authority.
- Annexure—V Form of Letter of Credit (applicable to Physical Imports).
- Annexure—VI Form of Letter of Credit (applicable to Services).

ANNEXURE I

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES

A. Developing Countries and Territories.

(a1) Non-OPEC Developing Countries.

I. Africa, North of Sahara :

Egypt
Morocco
Tunisia

II. Africa, South of Sahara .

Angola
Botswana
Burundi
Cameroon
Cape Verde Islands
Central African Rep.
Chad
Comoro Islands
Congo, People's Republic of Dahomey
Equatorial Guinea (1)
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Malagasy Republic
Malawi
Mali
Mauritania, Mauritius
Mozambique
Niger
Portuguese Guinea
Reunion
Rhodesia
Rwanda
St. Helena and dep. (2)
Sao Tomo and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Swaziland

Togo, Afars and Issas
Togo
Uganda
Un. Rep. of Tanzania
Upper Volta
Zaire Republic
Zambia

III. America, North & Cent. :

Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
El Salvador
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
St. Pierre & Miquelon
Trinidad and Tobago

- (1) Formerly the territory of Spanish Guinea, including the island of Fernando Po.
- (2) Including the following islands: Ascension, Tristan da Inaccessibles, Nightingale, Gough.
- (3) Main islands. Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, St. Eustacit St. Martin (Southern Part).

America, North & Central (Continued)

West Indies (Br.) n.i.e.

- (a) Associated States (1)
- (b) Dependencies (2)

IV. America, South

Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Falkland Islands
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay

V. Asia, Middle East :

Bahrain
Israel
Jordan
Lebanon
Oman
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates (3)
Yemen Arab Republic
Yemen, People's D.R. (4)

VI. Asia, South :

Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Burma
India
Maldivis
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

VII. Asia, Far East :

Brunei
Hong Kong
Khmer Republic
Korea, Republic of Laos
Macao
Malaysia
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Timor
Viet-Nam, Rep. of
Viet-Nam Dem. Rep.

VIII. Oceania :

Cook Islands
Fiji
Gilbert & Ellice Is.
French Polynesia (5)
Neura
New Caledonia
New Hebrides (Br. and Fr.)
Niue
Pacific Islands (US) (6)
Papua New Guinea
Solomon Islands (Br.)
Tonga
Wallis and Futuna
Western Samoa

IX. Europe :

Cyprus
Gibraltar
Greece
Malta
Spain
Turkey
Yugoslavia

- (1) Main islands: Antigua, Dominica, Grenada, St. Kitts (St. Christopher), Nevis-Anguilla, St. Lucia and St. Vincent.
- (2) Main islands: Montserrat, Cayman, Turks and Caicos, and British Virgin Islands.
- (3) Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah and Umm al Quaiwain.
- (4) Including Aden and various sultanates and emirates.
- (5) Comprising the Society Islands (including Tahiti), The Austral Islands, the Tuamotu-Gambier Group and the Marquesas Islands.
- (6) Trust Territory of the Pacific Islands: Caroline Islands, Marshall Islands, and Marine Islands (except Guam).

(a2) Member or Association Countries of OPEC :

Algeria
Bolivia
Libyan Arab Republic
Gabon
Nigeria
Ecuador
Venezuela
Iran
Iraq
Kuwait
Qatar
Saudi Arabia
Abu Dhabi
Indonesia

ANNEXURE-II

MAIN GUIDELINES FOR 'PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES UNDER THE PROJECT LOAN AS FORMULATED BY O.E.C.F.

I. Advertising :

For all contracts subject to Formal Open International Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least one newspaper of general circulation in India.

II. Bidding Documents and Contracts :

II-1. Bid Bonds or Guarantees :

Bid Bonds or bidding guarantees are a usual requirement but they should not be set so high as to discourage suitable bidders. Bid bonds or guarantees should be released to unsuccessful bidders as soon as possible after the bid have been opened.

II. 2. Condition of Contract :

The conditions of contract should clearly define the rights and obligations of the importer and the contractor or supplier, and the powers and authority of the engineer, if one is employed by the importer, in the administration of the contract and any variations thereunder. In addition to the customary general conditions of contract, some of which are referred to in these Guidelines, special conditions appropriate to the nature and location of the project should be included.

II. 3 Type and Size of Contract :

Contracts can be let on the basis of unit prices for work performed or items supplied or of a lump sum price, or a combination of both for different portion of the contract, according to the nature of the goods or services to be provided and the bidding documents should clearly state the type of contract selected.

Contracts based principally on the reimbursement of actual costs are not acceptable by the Fund except in exceptional circumstances.

Single contracts for engineering, equipment and construction to be provided by the same party ("Turnkey Contracts") are acceptable if they offer technical and economic advantages for the borrower country.

II-4. Eligible suppliers :

Exporters or suppliers whose goods and services are to be financed out of the proceeds of the Loan (hereinafter referred to as "the eligible supplier") shall be nationals of the eligible source countries satisfying the following conditions.

- (1) a majority of subscribed shares shall be held by nationals of the eligible source countries,
- (2) a majority of full-time directors shall be nationals of the eligible source countries and
- (3) such juridical 'persons' shall be registered in the eligible source countries.

III-1. Contract Price :

(a) The contract price should be stated in Japanese Yen provided, however, that the portion of the contract price which the contractor will spend in the borrower's country should be stated in the borrower's currency.

(b) Price Adjustment Clauses :
Bidding documents should contain a clear statement whether firm prices are required or escalation of the bid prices is acceptable.

A provision should be made for adjustment in the contract prices in the event changes occur in the prices of the major cost constituents of the contract, such as labour and important materials.

The specific formula for price adjustments should be clearly defined in the bidding documents.

A ceiling on price adjustment should be included in contracts for the supply of goods, but it is not usual to include such a ceiling in contracts for civil works.

No price adjustments should normally be provided for goods to be delivered within one year.

The Guidelines do not attempt to identify the various methods by which contract prices may be adjusted.

(c) Insurance :

The bidding documents should state precisely the types of insurance to be provided by the successful bidder.

III-2. The contract duly signed by both parties or purchase order by the Indian importer placed on the overseas supplier supported by order confirmation in writing by the overseas supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund.

III-3. The following statement of eligibility by the supplier shall be added to each contract:

"I (We) hereby state that my (our) company is an eligible supplier, as _____ per cent (%) of the shares are held by nationals of _____ (eligible source country), and _____ percent () of the directors are nationals _____ (eligible source country) and my (our) company has been registered in _____ (eligible source country)".

IV-1. Standards :

If national standard to which equipment or materials must comply are cited, the specifications should state that commodities meeting Japan Industrial Standard or other internationally accepted standards, which ensure an equal or higher quality than the standards mentioned, will also be accepted.

IV-2. Use of Brand Names :

Specifications should be based on performance capability and should only prescribe brand names, catalogue numbers, or products of specific manufacturer if specific spare parts are required or it has been determined that a degree of standardization is necessary to maintain certain essential features. In the latter case the specifications should permit offers of alternative commodities which have similar characteristics and provide performance and quality at least equal to those specified.

IV-3. Guarantees, Performance Bonds and Retention Money :

Bidding documents for civil works should require some form of surety to guarantee that the work will be continued until it is completed. This surety can be provided either by a bank guarantee or by a performance bond, the amount of which will vary with the type and magnitude of the work, but should be sufficient to protect the borrower in case of default by the contractor. Its life should extend sufficiently beyond completion of the contract to cover a reasonable warranty period. The amount of the guarantee or bond required should be defined in the bidding documents.

In contracts for the supply of goods it is usually preferable to have a percentage of the total payment held as retention money to guarantee performance than to have a bank guarantee or bond. The percentage of the total payment to be held as retention money and the conditions for its ultimate payment should be stipulated in the bidding documents. If, however, a bank guarantee or bond is preferred it should be for a nominal amount.

V. Liquidated Damage :

Liquidated damage clauses should be included in bidding documents when delays in completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues or loss of other benefits to the borrower. Provision may also be made for a bonus to be paid to contractors for completion of civil works contracts at or ahead of times specified in the contract when such earlier completion would be of benefit to the borrower.

VI. Force Majeure :

The conditions of the Contract included in the bidding documents should contain clauses, when appropriate, stipulating that a failure on the part of the parties to perform their obligations under the Contract shall not be considered a default under the Contract if such failure is the result of an event of force majeure (to be defined in the conditions of the Contract).

VII. Settlement of Disputes :

Provision dealing with the settlement of disputes should be included in the conditions of the Contract. It is desirable that the provisions should be based on "Rules of Conciliation and Arbitration" which have been prepared by the International Chamber of Commerce or on such other arrangements as may be mutually acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier.

VIII. Language Interpretation :

Bidding documents should be prepared in English. If other language should be used in the bidding documents, English should be added to such documents and it is required to specify which is governing.

IX. Bid Opening, Evaluation and Award of Contract :

IX. 1. Time Interval between Invitation and Submission of bids.—Time allowed for preparation of bids will depend to a large extent upon the magnitude and complexity of the contract. Generally not less than 30 days should be allowed for international bidding. The time allowed, however, should be governed by the circumstances relating to each contract.

IX. 2. Bid Opening Procedures.—The date, hour and place for the latest receipt of bids and for the bid opening should be announced in the invitations to bid and all bids should be opened publicly at the stipulated time. Bids received after this time should be returned unopened. The name of the bidder and the total amount of each bid and of any alternative bids, if they have been requested or permitted, should be read aloud and recorded.

IX. 3. Clarifications or Alternation of Bids.—No bidder should be permitted to alter his bid after the bids have been opened. Only clarifications not changing the substance of the bid may be accepted. The importer may ask any bidder to change the substance or the price of his bid.

IX. 4. Procedures to be confidential.—Except as may be required by law, no information relating to the examination, clarification and evaluation of bids and recommendations concerning award should be communicated after the public opening of bids to any persons not officially concerned with these procedures until the award of a contract to the successful bidder is announced.

IX. 5. Examination of Bids.—Following the opening, it should be ascertained whether material errors in computation have been made in the bids, whether the bids are fully responsive to the bidding documents, whether the required sureties have been provided, whether documents have been

properly signed and whether the bids are otherwise generally in order. If a bid does not substantially conform to the specifications, or contains inadmissible reservations, or is not otherwise substantially responsive to the bidding documents, it should be rejected. A technical analysis should then be made to evaluate each responsive bid and to enable bids to be compared.

IX. 6. Post-qualification of Bidders.—In the absence of prequalifications, the borrower should determine whether the bidder whose bid has been evaluated the lowest has the capability and financial resources effectively to carry out the contract concerned. If the bidder does not meet that test, his bid should be rejected.

IX. 7. Evaluation and Comparison of Bids.—Bid evaluation must be consistent with the terms and conditions set forth in the bidding documents. In addition to the bid price, adjusted to correct arithmetical errors other factors such as the time of completion of construction or the efficiency and compatibility of the equipment, the availability of service and spare parts, and the reliability of construction methods proposed should be taken into consideration. To the extent practicable these factors should be expressed in monetary terms according to criteria specified in the bidding documents. The amount of escalation for price adjustments, if any, included in the bids should not be taken into consideration.

The currency or currencies in which the price offered in each bid would be paid by the borrower if that bid were accepted should be valued in terms of a single currency selected by the borrower for comparison of all bids and stated in the bidding documents. The rates of exchange to be used in such valuation should be the selling rates published by an official source, and applicable to similar transactions on the day bids are opened unless there should be a change in the value of currencies before the award is made. In such cases the exchange rates at the time of the decision to notify the award to the successful bidder should be used.

IX. 8. Rejection of Bids.—Bidding documents usually provide that borrowers may reject all bids. However, all bids should not be rejected and new bids invited on the same specifications solely for the purpose of obtaining lower prices in the new bids, except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the costs estimates by a substantial amount. Rejection of all bids may also be justified when (a) bids are not responsive to the intent of the bidding documents, or (b) there is a lack of competition. If all bids are rejected, the borrower should review the cause or causes justifying the rejection and either consider revision of the specifications or modifications in the project (or amounts of work on items called for in the original invitation to bids), or both. In special circumstances, after consultation with the Fund, the borrower may negotiate with one or two of the lowest bidders to try to obtain a satisfactory contract.

IX. 9. Award of Contract.—The Award of a contract should be made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated bid and who meets the appropriate standards of capability and financial resources. Such bidder should not be required, as a condition of award, to undertake responsibilities on commodities not stipulated in the specifications or to modify his bid.

ANNEXURE III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No. _____ Date _____

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street, New Delhi-110001.

Subject :—Import of _____ from under the
Yen Credit OECF Loan Agreement No. _____

Sir,

In connection with the import of _____ from
_____ under the above mentioned Yen Credit

OECF Loan Agreement No. _____ we furnish the following particulars to enable you to issue the Letter of Authority to the _____ [name of the Bank which should be the same as given in (p) below] for opening a letter of credit in favour of the overseas suppliers concerned —

- (a) Name and Address of the Indian importer
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid
- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International Tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any
- (d) Brief description of the goods
- (e) Origin of the goods
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any
- (g) Gross C&F value of contract (in Yen)
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.
- (i) Net C&F value in Yen payable to Overseas Suppliers for which the Letter of Authority is required
- (j) Number and date of the contract.
- (k) Name and Address of the Overseas Supplier.
- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due
- (m) Expected date of completion of deliveries
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal)
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/ part-shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and Address of the importer's bank in India
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities, and if so, the Number, date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF
- (r) Whether the banking charges payable to Bank of India, Tokyo for operation and maintenance of Letter of Credit are to be borne by the Importer/Supplier.

- (c) Method of procurement—whether it is based on direct purchase or Formal Open International Tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any
- (d) Brief description of the goods
- (e) Origin of the goods
- (f) Percentage of the import components from non-eligible source countries, if any.
- (g) Gross FOB value of contract (in Yen)
- (h) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any.
- (i) Net FOB value (in Yen) for which the Letter of Authority is required.
- (j) Number and date of the contract with overseas suppliers
- (k) Name and Address of the overseas supplier :
 - (i) Nationality
 - (ii) Percentage of the shares held by nationals of the eligible source countries
 - (iii) Nationality of the representative and/or President of the supplier
 - (iv) Percentage of Directors who are nationals of eligible source countries
- (l) Payment terms and probable dates on which payments under the contract will fall due.
- (m) Expected date of completion of deliveries
- (n) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (o) Shipment instructions (indicate if trans-shipment/ part shipment permitted or not permitted).
- (p) Name and address of the importer's bank in India
- (q) Whether a contract(s) under the same licence has been placed and notified to the Japanese authorities and if so, the No., date and value of each such contract and the reference of the Ministry of Finance under which it has been notified to the OECF
- (r) Whether the Banking charges payable to B O I Tokyo for opening, maintenance and operation of Letter of Credit will be borne by the importer/supplier
- (s) Undertaking by the importer —

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc. of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers are approved by us and the payments made to the suppliers."

ANNEXURE IV

(Letter of Authority Form)

No F

Government of India
Ministry of Finance

Department of Economic Affairs
New Delhi, the 198

To

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan)

Subject—Import under Yen Credit (Project Aid)— Loan Agreement No. _____ Issue of Letter of Authority for opening Letter of Credit.

Dear Sirs

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 25.3.1980 entered into with your Bank You

ANNEXURE III

REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF AUTHORITY

No Date

To

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
UCO Bank Building, 1st Floor,
Parliament Street,
New Delhi-110001

Subject—Import of _____ from Japan under the Yen Credit No. _____ (Project Aid).

Sir,

In connection with the import of _____ from _____ under the above mentioned Yen credit No. _____ (Project Aid) we furnish the following particulars to enable you to issue the letter of Authority to the _____ (name of the Bank) which should be the same as given in (p) below for opening a Letter of Credit in favour of overseas supplier concerned

- (a) Name and Address of the Indian importer
- (b) Number, date and value of the import licence and date upto which it is valid

are hereby authorised to open irrevocable Letter of Credit for an amount not exceeding Yen _____ favouring M/s. _____ as per attached details.

A copy each of the letter of credit opened by your Bank may be endorsed to the importer's Bank to the O.E.C.F. Embassy of India, Tokyo and to us.

Payments to the suppliers in terms of the letter of credit will be made initially out of your own funds. After payments, you must claim immediately re-imbursements of the amounts paid by furnishing necessary documents to the OECF.

For the time lag between the dates of payment by you to the supplier and the date of its reimbursement by the OECF, You will be paid interests as per terms of the above agreement by the Embassy of India, Tokyo. The other banking charges including those on account of opening, maintenance and for the operation of the Letter of Credit as also those connected with handling negotiating documents and charges of overseas suppliers bankers if any, are to be borne by the importer/overseas suppliers. As such no reimbursement of such charges is to be claimed from the OECF.

As and when any payment is made by you and reimbursement is made to you, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry.

This Letter of Authority is intended for opening of L/C favouring the overseas suppliers. Subsequent amendments to L/C or further fresh L/Cs against this authorisation may not be acted upon in the absence of a specific authority from this Ministry.

This Letter of Authority will remain valid upto—

Yours faithfully,
(Accounts Officer)

Copy forwarded to :—

1. Importer _____ with reference to their letter No. _____ dated _____.

They are requested to arrange to deposit through their Bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner, before taking delivery of the negotiable documents from the Bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the Licensing Conditions.

2. Importer's Banker _____. They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the overseas suppliers on receipt of documents from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to overseas suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC (PN)/76 dated 17-1-1976 or such other Public Notices as may be issued from time to time. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import documents are handed over to the importer for Customs clearance.

These amounts should be deposited either with the RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or the S.B.I., Tis Hazari, Delhi. In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notices No. 184-ITC(PN)/68 dated 30-8-68, 233-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968, 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971, No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-5-1974 and No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. The head of Account to be credited is "K-Deposits and Advances—843—Civil Deposits—Deposit for purchases etc., abroad under Purchases under Credit/Loan Agreements"—Loans from the Government of Japan—543 billion Yen Credit (Project Aid) No ID-P 27 for 1983-84.

One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi, or the SBI Tis Hazari Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC (PN)/71 dated 5-10-1971 should be sent by them to the address given below along with a

forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

2. The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), 1st Floor, UCO Bank Building, Parliament Street, New Delhi-1.

In case where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24-10-1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited should be furnished to this Department.

The banking charges, interest and other charges of the Bank of India, Tokyo Branch (including charges of the overseas suppliers bankers), if any, should be settled by paying their rupee equivalents to the Principal Accounts Officer in the Ministry of External Affairs, New Delhi. For this purpose appropriate advices will be sent by this Department on receipt of relevant information from the Bank of India, Tokyo/Embassy of India in Japan.

3. The Director, Loan Department-II, Overseas Economic Cooperation Fund, Takebashi Godo Building, 4-1, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan.

4. Embassy of India, Tokyo.

5. The Under Secretary, Japan Section, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi.

Accounts Officer

ANNEXURE V

Form OECF-LC I

Irrevocable Letter of Credit
(Applicable for goods)

Date :

To

(Name and address of the Supplier).

This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____ dated _____ between (Borrower) and the Overseas Economic Cooperation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable Credit No. _____ in your favour for account of _____ for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y _____ (say Yen _____) available by your drafts at sight for full invoice value drawn on us, to be accompanied by the following documents :—

Signed commercial invoice in

Full set of clean on board ocean bills of lading made out to order and blank endorsed and marked "Freight" and "Notify"

Other documents.

evidencing shipment of (brief description of goods to be shipped referring to Contract No. _____ (if any) from _____ to _____ Partial shipments are _____ Permitted. Trans-shipment is _____ permitted.

Bills of lading must be dated not later than

Drafts must be presented for negotiation not later than

All drafts and documents under this credit must be marked "Drawn under _____ irrevocable credit No. _____ dated _____ and Import Reference No. _____ (s). (if any)".

This credit is not transferrable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision)". International Chamber of Commerce Publication No. 290."

Special Instruction to the negotiating bank :

1. After obtaining the reimbursement for our payments from The Overseas Economic Cooperation Fund in

accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above-mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank.

2. The negotiating bank must forward the drafts and one complete set of documents to us together with the certificate stating that the remaining documents have been airmailed direct to—
3. All banking charges under this Credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully
(commercial bank)

By : _____
(Authorised Signature)

PAYMENT TERMS

This payment terms constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount : Y _____
being _____% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

II. Intermediate Payment (if any)

Amount : Y _____
being _____% of the total contract price.

Required documents :

Latest presentation date :

III. Payment against Shipping Documents

Amount : Y _____
being _____% of the total contract price.

Note.—Th's attached sheet is not required in case of full payment against Shipping Documents.

ANNEXURE VI

Form OECF-LC II

Irrevocable Letter of Credit

(Applicable for Services)

Date :

To,

(Name and address of the Supplier). This letter of credit has been issued pursuant to Loan Agreement No. _____ dated _____ between (Borrower) and the Overseas Economic Cooperation Fund.

Dear Sirs,

We advise you that we have opened our irrevocable credit No. _____ in your favour for account of for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of Y _____ (Say Yen _____) available by beneficiary's drafts at sight for full Statement value drawn on us.

To be accompanied by the required documents, in accordance with the Payment Schedule attached hereto, concerning (Contract No. _____) with regard to Project). Drafts must be presented for negotiation not later than _____.

All drafts and documents must be marked "Drawn under irrevocable credit No. _____ dated _____".

This credit is not transferable.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

Unless otherwise expressly stated, this credit is subject to "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 Revision) International Chamber of Commerce Publication No. 290".

Special Instructions to the negotiating bank :

1. After receipt of the original Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority) in accordance with the form attached hereto, payment(s) under this credit must be made in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached hereto. In case of the initial payments, the beneficiary's Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Performance.
2. After obtaining the reimbursement for our payment from The Overseas Economic Cooperation Fund in accordance with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the above mentioned Loan Agreement, we undertake to remit the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank.
3. A copy of the document as mentioned in item 1 above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipts thereof.
4. All banking charges under this credit are for the account of the importer/supplier.

Yours faithfully,
(a commercial bank)

By : _____
(Authorised Signature)

PAYMENT SCHEDULE

This payment schedule constitutes an integral part of our Letter of Credit No. _____.

I. Initial Payment

Amount : Y _____
being _____% of the total contract price.

Required documents : beneficiary's Statement Latest presentation date :

II. Progress Payment

Aggregate amount : Y _____
being _____% of the total contract price to be paid as follows :

Amount due Latest presentation date

1st Instalment : Y _____

2nd instalment : Y _____

Required documents : a copy of Statement of Performance issued by (Borrower or its designated authority), a form of which is attached hereto.

Statement of Performance

Date :

To Ref No.

(Name and address of the Supplier),

Re : Letter of Credit No. _____ dated _____ issued by _____ for Y _____ in favour of _____ concerning _____ Project, under Loan Agreement No. _____.

1. the undersigned, representing (Borrower) hereby issue a Statement of Performance to entitle _____, to receive the sum of Y _____ (Yen _____ only) from The Overseas Economic Cooperation Fund in accordance with the Payment Terms stipulated in the Contract No. _____, dated _____, between _____ and _____.

(Borrower)

By : _____
(Authorised Signature)

Special Instructions :

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto.